IJMSERH

International Journal of Multidisciplinary and Scientific Emerging ResearcH (IJMSERH)

Volume 14, Issue 2, April-June 2026

Impact Factor: 9.274

ROAD
INNO SPACE
SJIF Scientific Journal Impact Factor
doi
Crossref

International Journal of Multidisciplinary and Scientific Emerging ResearcH (IJMSERH)

| ISSN: 2349-6037 | www.ijmserh.com ||Impact Factor: 9.274||Quarterly, Peer Reviewed & Refereed Journal|

|| Volume 14, Issue 2, April-June 2026 ||

DOI: 10.15662/IJMSERH.2026.1402036

न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और किसानों की आय: एक आर्थिक विश्लेषण

डॉ. सुनीता बेनीवाल

सहायक आचार्य (अर्थशास्त्र)

राजकीय कन्या महाविद्यालय, हेतमसर, झुंझुनू

सारांश

भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ आज भी बड़ी जनसंख्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। कृषि क्षेत्र न केवल देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और रोजगार का भी प्रमुख आधार है। किंतु पिछले कुछ दशकों में किसानों को अनेक आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, जैसे उत्पादन लागत में निरंतर वृद्धि, कृषि उपज के मूल्य में अस्थिरता, प्राकृतिक जोखिम तथा बाजार की अनिश्चितता। इन परिस्थितियों में किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करने तथा कृषि आय को स्थिर बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था लागू की गई। न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) वह न्यूनतम मूल्य है, जिस पर सरकार किसानों से उनकी कृषि उपज खरीदने की गारंटी प्रदान करती है, ताकि बाजार में कीमतों में गिरावट की स्थिति में भी किसानों को आर्थिक सुरक्षा मिल सके। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की घोषणा प्रत्येक वर्ष कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP) की सिफारिशों के आधार पर की जाती है। वर्तमान में सरकार लगभग 23 प्रमुख फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) निर्धारित करती है, जिनमें गेहूं, धान, दालें, तिलहन और कुछ अन्य प्रमुख फसलें शामिल हैं। सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का उद्देश्य किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान करना, कृषि उत्पादन को प्रोत्साहित करना तथा कृषि क्षेत्र में आय की स्थिरता बनाए रखना है। प्रस्तुत शोध-पत्र में न्यूनतम समर्थन मूल्य और किसानों की आय के मध्य संबंध का आर्थिक विश्लेषण किया गया है। अध्ययन में यह समझने का प्रयास किया गया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) नीति किसानों को किस हद तक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है और यह उनकी आय को किस प्रकार प्रभावित करती है।

मुख्य शब्द : एमएसपी, कृषि नीति, कृषि मूल्य, भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था।

| ISSN: 2349-6037 | www.ijmserh.com ||Impact Factor: 9.274||Quarterly, Peer Reviewed & Refereed Journal|

|| Volume 14, Issue 2, April-June 2026 ||

DOI: 10.15662/IJMSERH.2026.1402036

प्रस्तावना :

भारतीय कृषि व्यवस्था लंबे समय से मूल्य अस्थिरता और बाजार संरचना से जुड़ी समस्याओं से प्रभावित रही है। कृषि उत्पादन मुख्यतः प्राकृतिक परिस्थितियों पर निर्भर होने के कारण इसमें अनिश्चितता अधिक होती है। वर्ष विशेष में यदि उत्पादन अधिक हो जाता है तो बाजार में आपूर्ति बढ़ने के कारण कृषि उपज के दाम गिर जाते हैं, जबकि उत्पादन कम होने पर कीमतों में तेजी देखी जाती है। इस प्रकार कृषि क्षेत्र में मूल्य अस्थिरता किसानों की आय को सीधे प्रभावित करती है। विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों के लिए यह स्थिति अधिक चुनौतीपूर्ण होती है, क्योंकि उनकी उत्पादन क्षमता सीमित होती है और वे बाजार के उतार-चढ़ाव को सहन करने में सक्षम नहीं होते। भारत में कृषि विपणन की पारंपरिक संरचना भी किसानों की आय को प्रभावित करती रही है। कई क्षेत्रों में किसान अपनी उपज को स्थानीय व्यापारियों या बिचौलियों के माध्यम से बेचते हैं, जिसके कारण उन्हें अपनी फसल का पूर्ण आर्थिक लाभ नहीं मिल पाता। इसके अतिरिक्त भंडारण सुविधाओं की कमी, परिवहन लागत और बाजार तक सीमित पहुँच भी किसानों की आय को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं। इन परिस्थितियों में कृषि मूल्य नीति की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इसके माध्यम से सरकार किसानों को एक निश्चित आर्थिक संरक्षण प्रदान करने का प्रयास करती है।

भारतीय कृषि मूल्य नीति का एक महत्वपूर्ण घटक न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी)) है, जिसके माध्यम से सरकार कृषि उत्पादों के लिए एक मानक मूल्य स्तर निर्धारित करती है। यह नीति कृषि उत्पादन को स्थिर बनाए रखने और किसानों को बाजार जोखिम से आंशिक सुरक्षा देने के उद्देश्य से विकसित की गई है। समय के साथ-साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) व्यवस्था भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण संस्थागत तंत्र बन गई है, जिसका संबंध केवल मूल्य निर्धारण से ही नहीं बल्कि खाद्य सुरक्षा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और कृषि उत्पादन संरचना से भी जुड़ा हुआ है। विगत वर्षों में किसानों की आय और कृषि क्षेत्र की स्थिरता को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक चर्चा हुई है। विभिन्न नीतिगत दस्तावेजों और अध्ययनों में यह प्रश्न उठाया गया है कि कृषि क्षेत्र में आय वृद्धि की गति अपेक्षाकृत धीमी क्यों है और किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए कौन-कौन से नीतिगत उपाय प्रभावी हो सकते हैं। इस संदर्भ में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) नीति को एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में देखा जाता है, क्योंकि इसका सीधा संबंध कृषि मूल्य, उत्पादन प्रोत्साहन और आय सुरक्षा से है।

| ISSN: 2349-6037 | www.ijmserh.com ||Impact Factor: 9.274||Quarterly, Peer Reviewed & Refereed Journal|

|| Volume 14, Issue 2, April-June 2026 ||

DOI: 10.15662/IJMSERH.2026.1402036

अध्ययन के उद्देश्य :

प्रस्तुत अध्ययन के विशिष्ट उद्देश्य निम्नलिखित हैं—

1. भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य की भूमिका और महत्व का अध्ययन करना।
2. प्रमुख फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में समयानुरूप हुए परिवर्तनों का विश्लेषण करना।
3. न्यूनतम समर्थन मूल्य और किसानों की आय के बीच संबंध का आर्थिक विश्लेषण करना।

आंकड़ों के स्रोत :

अध्ययन मुख्यतः द्वितीयक आँकड़ों पर आधारित है, जिन्हें विभिन्न सरकारी रिपोर्टों, आर्थिक सर्वेक्षणों, कृषि मंत्रालय की प्रकाशन सामग्री, नीति आयोग की रिपोर्टों तथा संबंधित शोध-पत्रों और पुस्तकों से संकलित किया गया है। संकलित आँकड़ों का विश्लेषण वर्णनात्मक तथा विश्लेषणात्मक पद्धति के माध्यम से किया गया है, जिससे न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के प्रभाव को व्यापक आर्थिक संदर्भ में समझा जा सके।

न्यूनतम समर्थन मूल्य की अवधारणा :

कृषि उत्पादों के मूल्य में होने वाले उतार-चढ़ाव का सीधा प्रभाव किसानों की आय और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। इसी संदर्भ में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी)) की अवधारणा विकसित हुई, जिसका उद्देश्य कृषि उत्पादों के लिए एक न्यूनतम मूल्य स्तर निर्धारित करना है। न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) निर्धारित करते समय सरकार केवल किसानों के हितों को ही नहीं बल्कि व्यापक आर्थिक परिस्थितियों और बाजार की संरचना को भी ध्यान में रखती है। इस प्रक्रिया में अनेक आर्थिक कारकों का विश्लेषण किया जाता है, जिनमें उत्पादन लागत, बाजार में मांग-आपूर्ति की स्थिति, कृषि और गैर-कृषि क्षेत्रों के बीच मूल्य संतुलन, उपभोक्ताओं और किसानों के हितों का संतुलन तथा अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थिति विशेष रूप से महत्वपूर्ण माने जाते हैं।

International Journal of Multidisciplinary and Scientific Emerging ResearcH (IJMSERH)

| ISSN: 2349-6037 | www.ijmserh.com ||Impact Factor: 9.274||Quarterly, Peer Reviewed & Refereed Journal|

|| Volume 14, Issue 2, April-June 2026 ||

DOI: 10.15662/IJMSERH.2026.1402036

1. उत्पादन लागत - कृषि उत्पादन में बीज, उर्वरक, कीटनाशक, सिंचाई, मशीनरी, श्रम तथा भूमि उपयोग से संबंधित विभिन्न खर्च शामिल होते हैं। यदि किसानों को इन लागतों से कम मूल्य प्राप्त होता है तो उन्हें आर्थिक हानि उठानी पड़ती है। अतः न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) निर्धारण के अंतर्गत उत्पादन लागत के विभिन्न स्तरों जैसे प्रत्यक्ष लागत, पारिवारिक श्रम का मूल्य तथा भूमि का अवसर लागत को ध्यान में रखते हुए कृषि मूल्य नीति तैयार की जाती है।

2. बाजार में मांग और आपूर्ति - यदि किसी फसल का उत्पादन अधिक हो जाता है तो बाजार में उसकी आपूर्ति बढ़ जाती है, जिससे कीमतों में गिरावट आ सकती है। इसके विपरीत उत्पादन कम होने पर कीमतों में वृद्धि हो सकती है। ऐसी परिस्थितियों में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) किसानों को मूल्य गिरावट से आंशिक सुरक्षा प्रदान करता है।

3. कृषि और गैर-कृषि क्षेत्र के बीच मूल्य संतुलन - यदि कृषि उत्पादों के मूल्य लंबे समय तक कम बने रहते हैं, तो किसानों की आय अन्य क्षेत्रों की तुलना में कम हो जाती है और कृषि क्षेत्र में निवेश तथा श्रम की भागीदारी घट सकती है। इसलिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) नीति के माध्यम कृषि क्षेत्र को उचित आर्थिक महत्व मिले ऐसे प्रयास किए जाते है।

4. उपभोक्ताओं और किसानों के हितों का संतुलन - यदि कृषि उत्पादों के मूल्य अत्यधिक बढ़ जाते हैं तो इसका प्रभाव खाद्य वस्तुओं की कीमतों पर पड़ता है, जिससे उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ बढ़ सकता है। दूसरी ओर, यदि कीमतें बहुत कम रहती हैं तो किसानों को पर्याप्त आय प्राप्त नहीं होती। इसलिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) निर्धारण में यह प्रयास किया जाता है कि ऐसा संतुलित मूल्य निर्धारित किया जाए जिससे किसानों को उचित लाभ मिले और उपभोक्ताओं पर अत्यधिक मूल्य भार भी न पड़े।

5. अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थिति – विभिन्न कृषि उत्पादों का आयात-निर्यात अंतरराष्ट्रीय बाजार की परिस्थितियों से प्रभावित होता है। यदि अंतरराष्ट्रीय बाजार में किसी फसल का मूल्य बहुत कम है तो घरेलू बाजार पर भी उसका प्रभाव पड़ सकता है। इसी प्रकार वैश्विक स्तर पर कीमतों में वृद्धि होने पर निर्यात के अवसर बढ़ सकते हैं। इसलिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) निर्धारण करते समय अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थिति, वैश्विक मूल्य प्रवृत्तियों तथा व्यापार नीतियों को भी ध्यान में रखा जाता है।

| ISSN: 2349-6037 | www.ijmserh.com ||Impact Factor: 9.274||Quarterly, Peer Reviewed & Refereed Journal|
|| Volume 14, Issue 2, April-June 2026 ||
DOI: 10.15662/IJMSERH.2026.1402036

न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का किसानों की आय पर प्रभाव :

न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का किसानों की आय पर प्रभाव विभिन्न स्तरों पर देखा जा सकता है, जिनमें मूल्य सुरक्षा, उत्पादन में वृद्धि, कृषि निवेश में वृद्धि तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती जैसे पहलू विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं।

1. मूल्य सुरक्षा - जब बाजार में किसी कृषि उत्पाद की कीमत गिर जाती है, तब न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) किसानों के लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है। इससे किसानों को यह भरोसा मिलता है कि उनकी उपज एक निश्चित मूल्य से कम पर नहीं बिकेगी। इस प्रकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) किसानों को मूल्य अस्थिरता के नकारात्मक प्रभाव से बचाने में सहायक होता है और उनकी आय में अत्यधिक गिरावट की संभावना को कम करता है।

2. उत्पादन में वृद्धि - न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की व्यवस्था किसानों को यह विश्वास दिलाती है कि उनकी मेहनत का आर्थिक प्रतिफल सुनिश्चित रहेगा। परिणामस्वरूप किसान बेहतर बीज, उर्वरक और आधुनिक कृषि तकनीकों का उपयोग करके उत्पादन बढ़ाने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) नीति कृषि उत्पादन को प्रोत्साहित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

3. कृषि निवेश में वृद्धि - न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के कारण किसानों को भविष्य की आय के संबंध में कुछ हद तक आर्थिक आश्वासन मिलता है, जिससे वे सिंचाई सुविधाओं, कृषि उपकरणों, उन्नत बीजों तथा अन्य कृषि संसाधनों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित हो सकते हैं। इस प्रकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) अप्रत्यक्ष रूप से कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने में सहायक हो सकता है।

4. ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती - जब किसानों की आय में सुधार होता है तो उनकी क्रय-शक्ति बढ़ती है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में वस्तुओं और सेवाओं की मांग में वृद्धि होती है। इससे स्थानीय व्यापार, लघु उद्योग तथा सेवा क्षेत्र को भी प्रोत्साहन मिलता है। इस प्रकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के माध्यम से किसानों की आय में होने वाली वृद्धि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की समग्र गतिविधियों को भी सुदृढ़ करने में सहायक हो सकती है।

| ISSN: 2349-6037 | www.ijmserh.com ||Impact Factor: 9.274||Quarterly, Peer Reviewed & Refereed Journal|

|| Volume 14, Issue 2, April-June 2026 ||

DOI: 10.15662/IJMSERH.2026.1402036

तालिका 01 : भारत में प्रमुख फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्यमें वर्षवार हुये परिवर्तन

वर्ष	गेहूं	धान	अरहर (तूर)	सरसों	बाजरा
2014–15	1450	1360	4350	3100	1250
2015–16	1525	1410	4625	3350	1275
2016–17	1625	1470	5050	3700	1330
2017–18	1735	1550	5450	4000	1425
2018–19	1840	1750	5675	4200	1950
2019–20	1925	1815	5800	4425	2000
2020–21	1975	1868	6000	4650	2150
2021–22	2015	1940	6300	5050	2250
2022–23	2125	2040	6600	5450	2350
2023–24	2275	2183	7000	5650	2500

स्रोत: *Commission for Agricultural Costs and Prices (CACP), Government of India*
Agricultural Statistics at a Glance, Ministry of Agriculture

उक्त तालिक के द्वारा देश में समय-समय पर एमएसपी मूल्यों मे आए बदलावों को दर्शाया गया है। गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर दृष्टि डालें तो वर्ष 2014–15 में इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 1450 रुपये प्रति क्विंटल था, जो क्रमिक रूप से बढ़ते हुए वर्ष 2023–24 में 2275 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुँच गया। इस प्रकार लगभग एक दशक की अवधि में गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में लगभग 825 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है। यह वृद्धि दर्शाती है कि सरकार गेहूं जैसी प्रमुख खाद्यान्न फसल के उत्पादन को बनाए रखने और किसानों को बेहतर मूल्य देने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। इसी प्रकार धान (कॉमन) के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में भी उल्लेखनीय वृद्धि देखी जा सकती है।

आरेख 01 : भारत में गेहूं एवं धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य

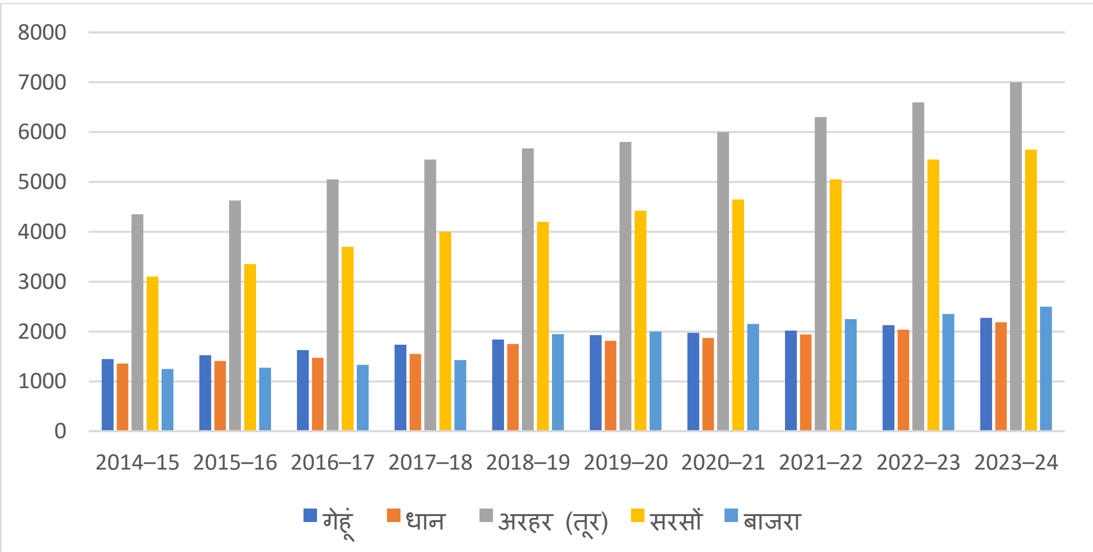

| ISSN: 2349-6037 | www.ijmserh.com ||Impact Factor: 9.274||Quarterly, Peer Reviewed & Refereed Journal|

|| Volume 14, Issue 2, April-June 2026 ||

DOI: 10.15662/IJMSERH.2026.1402036

वर्ष 2014–15 में धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 1360 रुपये प्रति क्विंटल था, जो वर्ष 2023–24 में बढ़कर 2183 रुपये प्रति क्विंटल हो गया। धान भारत की सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है, इसलिए इसके न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में निरंतर वृद्धि का उद्देश्य देश की खाद्य सुरक्षा को बनाए रखना तथा किसानों को उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करना है। दलहन फसलों के संदर्भ में अरहर (तूर) के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में भी महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2014–15 में अरहर का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 4350 रुपये प्रति क्विंटल था, जो वर्ष 2023–24 में बढ़कर लगभग 7000 रुपये प्रति क्विंटल हो गया। दलहन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि का मुख्य उद्देश्य देश में दालों के उत्पादन को बढ़ावा देना तथा आयात पर निर्भरता को कम करना है। इसी प्रकार तिलहन फसलों में सरसों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में भी क्रमिक वृद्धि देखी जा सकती है। वर्ष 2014–15 में सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 3100 रुपये प्रति क्विंटल था, जो वर्ष 2023–24 में बढ़कर 5650 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुँच गया। तिलहन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि का उद्देश्य देश में खाद्य तेलों के घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करना और विदेशी आयात पर निर्भरता को कम करना है। तालिका में शामिल मोटे अनाज (बाजरा) के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में भी उल्लेखनीय वृद्धि देखी जा सकती है। वर्ष 2014–15 में बाजरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 1250 रुपये प्रति क्विंटल था, जो वर्ष 2023–24 में बढ़कर 2500 रुपये प्रति क्विंटल हो गया। मोटे अनाज के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में वृद्धि का एक प्रमुख कारण सरकार द्वारा इन फसलों को पोषणयुक्त तथा जलवायु-अनुकूल फसल के रूप में बढ़ावा देना है। इससे किसानों को फसल विविधीकरण के लिए भी प्रोत्साहन मिलता है।

तालिका 02 : एमएसपी से पूर्व और पश्चात किसानों की औसत मासिक आय

वर्ष	किसानों की औसत मासिक आय (रुपये)
1955	100
1965	170
1980	500
2003	2,115
2013	6,426
2019	10,218
2022	11,000

स्रोत : *NSSO Situation Assessment Survey (2003, 2013, 2019), NABARD Rural Financial Inclusion Survey, Economic Survey of India & CACP Reports*

| ISSN: 2349-6037 | www.ijmserh.com ||Impact Factor: 9.274||Quarterly, Peer Reviewed & Refereed Journal|

|| Volume 14, Issue 2, April-June 2026 ||

DOI: 10.15662/IJMSERH.2026.1402036

आरेख 02 : एमएसपी से पूर्व और पश्चात किसानों की औसत मासिक आय

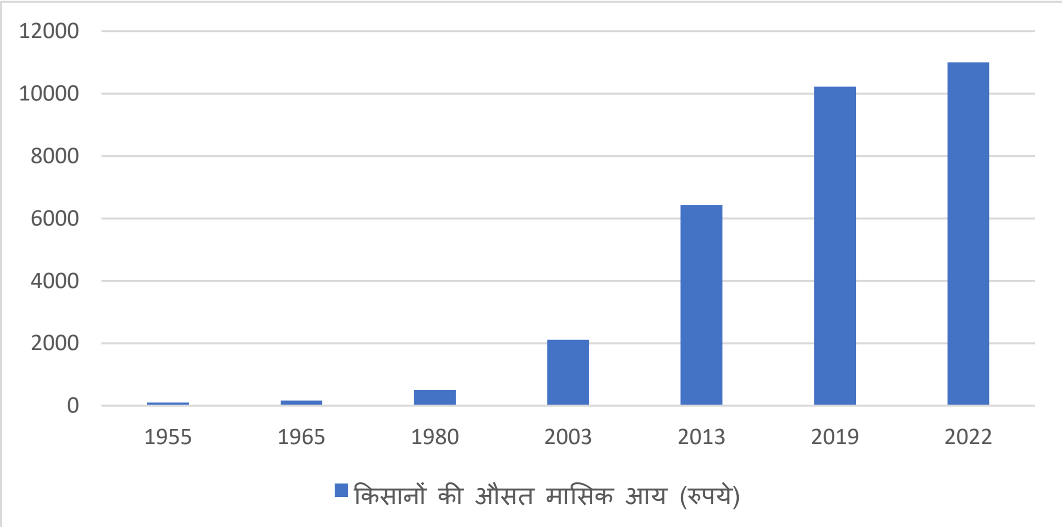

तालिका से यह स्पष्ट होता है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) नीति लागू होने से पहले किसानों की आय अपेक्षाकृत बहुत कम और अस्थिर थी। 1960 के दशक में औसत कृषक परिवार की मासिक आय लगभग 100 से 125 रुपये के बीच थी। न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) व्यवस्था लागू होने तथा हरित क्रांति के बाद कृषि उत्पादन और कृषि आय दोनों में वृद्धि देखी गई। बाद के वर्षों में कृषि तकनीक, सिंचाई सुविधाओं, सरकारी खरीद प्रणाली तथा विभिन्न कृषि योजनाओं के कारण किसानों की आय में धीरे-धीरे वृद्धि हुई। NSSO के अनुसार वर्ष 2003 में किसानों की औसत मासिक आय लगभग 2115 रुपये थी, जो 2019 तक बढ़कर लगभग 10218 रुपये प्रति माह हो गई। इससे यह संकेत मिलता है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और अन्य कृषि नीतियों ने किसानों की आय को स्थिर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, हालांकि आय वृद्धि की गति अभी भी अपेक्षाकृत धीमी मानी जाती है।

निष्कर्ष :

अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) व्यवस्था किसानों को मूल्य स्थिरता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह नीति विशेष रूप से उन किसानों के लिए सहायक सिद्ध होती है, जो सरकारी खरीद प्रणाली के अंतर्गत अपनी उपज बेचने में सक्षम होते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के कारण किसानों को फसल उत्पादन के समय न्यूनतम आय की एक निश्चित सुरक्षा प्राप्त होती है, जिससे कृषि में निवेश और उत्पादन की निरंतरता बनी रहती है। साथ ही यह नीति देश की खाद्य सुरक्षा को भी मजबूत बनाने में सहायक रही है।हालाँकि अध्ययन यह भी दर्शाता है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) व्यवस्था का लाभ देश के सभी किसानों तक समान रूप से नहीं पहुँच पाया है।

| ISSN: 2349-6037 | www.ijmserh.com ||Impact Factor: 9.274||Quarterly, Peer Reviewed & Refereed Journal|
|| Volume 14, Issue 2, April-June 2026 ||
DOI: 10.15662/IJMSERH.2026.1402036

सरकारी खरीद प्रणाली मुख्यतः कुछ राज्यों, जैसे पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिक प्रभावी रही है, जबकि कई अन्य राज्यों के किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं कर पाते। इसके अतिरिक्त न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का प्रभाव मुख्य रूप से गेहूं और धान जैसी फसलों तक सीमित दिखाई देता है, जिससे कृषि विविधीकरण पर भी कुछ हद तक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अतः यह आवश्यक है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) व्यवस्था को अधिक व्यापक और प्रभावी बनाया जाए, ताकि इसका लाभ देश के अधिकाधिक किसानों तक पहुँच सके। साथ ही कृषि बाजार संरचना में सुधार, सरकारी खरीद प्रणाली का विस्तार तथा किसानों को बेहतर बाजार सुविधाएँ उपलब्ध कराना भी अत्यंत आवश्यक है। यदि इन सुधारों को प्रभावी रूप से लागू किया जाए, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) नीति किसानों की आय बढ़ाने तथा कृषि क्षेत्र को आर्थिक रूप से अधिक सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

संदर्भ सूची :

1. Chand, R. (2017). *Doubling farmers' income: Rationale, strategy, prospects and action plan*. NITI Aayog.
2. Commission for Agricultural Costs and Prices. (2023). *Price policy for Kharif crops: The marketing season 2023–24*. Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India.
3. Food and Agriculture Organization. (2021). *Agricultural outlook 2021–2030*. FAO Publishing.
4. Government of India. (2023). *Agricultural statistics at a glance 2023*. Ministry of Agriculture and Farmers Welfare.
5. Government of India. (2023). *Economic survey of India 2022–23*. Ministry of Finance.
6. Gulati, A., & Saini, S. (2018). *Farm income in India: Myths and realities*. Indian Council for Research on International Economic Relations.
7. Kumar, P., Joshi, P. K., & Birthal, P. S. (2016). Agricultural growth and farmers' income in India: Issues and challenges. *Agricultural Economics Research Review, 29*(2), 203–215.
8. National Sample Survey Office. (2014). *Situation assessment survey of agricultural households in India*. Ministry of Statistics and Programme Implementation.
9. National Sample Survey Office. (2019). *Situation assessment of agricultural households and land and livestock holdings in India*. Ministry of Statistics and Programme Implementation.

| ISSN: 2349-6037 | www.ijmserh.com ||Impact Factor: 9.274||Quarterly, Peer Reviewed & Refereed Journal|

|| Volume 14, Issue 2, April-June 2026 ||

DOI: 10.15662/IJMSERH.2026.1402036

10. NITI Aayog. (2018). *Strategy for new India @75*. Government of India.
11. OECD & Food and Agriculture Organization. (2022). *OECD-FAO agricultural outlook 2022–2031*. OECD Publishing.
12. Swaminathan, M. S. (2007). *National commission on farmers: Final report*. Ministry of Agriculture, Government of India.

INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INDIA

INNO SPACE SJIF Scientific Journal Impact Factor

doi crossref

निस्केयर NISCAIR

International Journal of Multidisciplinary and Scientific Emerging Research (IJMSERH)

Impact Factor: 9.274

editor@ijmserh.com

www.ijmserh.com